

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 62/18

GCMS NO 2018/00066

1. श्रीमती तुलसा बेवा बदरी

2. जगदीश पुत्र बदरी

3. हंसराज पुत्र बदरी

4. राजय पुत्र बदरी

5. जितेन्द्र पुत्र बदरी

6. श्रीमति सणगारी बेवा हरकेश

7. अशोक पुत्र हरकेश नाबालिंग जरिये संरक्षिका माता सणगारी पत्नि स्व० हरकेश

8. महेन्द्र पुत्र हरकेश नाबालिंग जरिये संरक्षिका माता सणगारी पत्नि स्व० हरकेश समस्त

जातियान माली निवासीयान ग्राम मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांत

बनाम

1. रामस्वरूप

2. अमृतलाल

3. श्यामलाल पिसरान श्रीनारायण

4. मु० रामकन्या बेवा रामनारायण

5. बत्तिलाल पुत्र रामनारायण

6. शांतिलाल पुत्र रामनारायण

7. शंभूदयाल पुत्र रामनारायण

8. केसन्ती बेवा जगराम

9. रूपनारायण पुत्र मूल्या

10. सीताराम पुत्र मूल्या

11. घनश्याम पुत्र मूल्या

12. कैलाशी पुत्री मूल्या

13. प्रेम पुत्री मूल्या

14. माधो पुत्र घीस्या

15. प्रहलाद पुत्र घीस्या

16. कजोड पुत्र जन्सी

17. अम्बालाल पुत्र जन्सी समस्त जातियान माली निवासीयान ग्राम मलारना चौड तहसील

मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

रेस्यो०

(अपील विरुद्ध मु०नं० 464/81 निर्णय दिनांक 16.2.81 न्यायालय उप जिलाधीश सवाई माधोपुर)

अभिमाषक अपीला० श्री राधेश्याम बैष्णव

अभिमाषक रेस्यो० श्री विनोद अग्रवाल, श्री जयप्रकाश सेनी

दिनांक 19.5.2025



राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर


निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 16.2.81 न्यायालय उप जिलाधीश सवाई माधोपुर पेश की है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रामनिवास, कल्याण एवं मूल्या पिसरान नन्दा जाति माली एवं घीस्या, जिन्सी पिसरान श्योवक्स जाति माली साकिन मलारना चौड द्वारा राजस्व अभियान केम्प मलारना चौड में प्रार्थना पत्र धारा 53 आर टी एक्ट पेश कर आराजीयात संख्या 735, 735,736 एवं 737 वाके ग्राम मलारना चौड का बंटवारा करने हेतु अपील रजामंदी से मौके पर कब्जे अनुसार बंटवारा करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर सहमति के आधार पर बंटवारा किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।


अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूयेदार मिसल होने से लायके मंसूखी है। अपीलांट व रेस्पों संख्या 1 लगायत 13 के बुर्जगान रामनिवास, कल्याण, मूल्या पिसरान नन्दा माली की आराजीयात ग्राम मलारना चौड तहसील बौली में स्थित है। सम्वत 2046-2049 की जमाबंदी में तीनों भाईयो का हिस्सा बराबर बराबर का इन्द्राज हो रहा है। रामनिवास, कल्याण, मूल्या पिसरान नन्दा की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात ख0न0 719 रकबा 9 बीघा 2 विस्वा चाही, 1074 रकबा 12 विस्वा चाही, 1179 रकबा 2 विस्वा नहरी, 1200 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा चाही, 1203 रकबा 9 विस्वा चाही, 1205 रकबा 2 विस्वा चाही, 1244/2 रकबा 16 विस्वा चाही, 1245/2 रकबा 4 विस्वा गैरमुमकिन, 1246/2 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा चाही, 1247 रकबा 19 विस्वा चाही, 1248 रकबा 3 विस्वा नहरी, 1249 रकबा 2 विस्वा नहरी, 1250 रकबा 13 विस्वा नहरी, 1252 रकबा 13 विस्वा चाही, 1253 रकबा 4 विस्वा चाही, 1255 रकबा 13 विस्वा चाही, 1304 रकबा 3 विस्वा गैर मुमकिन बाडा, 1305 रकबा 2 विस्वा वाडा, 1482 रकबा 16 विस्वा चाही, 1487 रकबा 11 विस्वा नहरी, 1488 रकबा 19 विस्वा नहरी, 1489 रकबा 3 बीघा 3 विस्वा नहरी, 1504 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा, 1505 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा नहरी, 1506 रकबा 9 विस्वा नहरी, 1507 रकबा 13 विस्वा नहरी, 1508 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा नहरी, 1509 रकबा 7 विस्वा नहरी, 1510 रकबा 2 बीघा 19 विस्वा नहरी, 1514/2 रकबा 3 बीघा 17 विस्वा नहरी, 1541 रकबा 7 बीघा 13 विस्वा बारानी, 1542 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा बंजड, 1550 रकबा 6 बीघा 12 विस्वा बारानी, 1551/1 रकबा 16 विस्वा बंजड डोल कुल किता 40 कुल रकबा 65 बीघा 11 विस्वा वाके ग्राम मलारना चौड में स्थित है। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व अभियान में तीनों भाईयो का बंटवारा एक प्रार्थना पत्र पर ही आदेश देकर किया है। तीनों भाईयो रामनिवास, कल्याण, मूल्या के बराबर बराबर आराजीयात हिस्से में आनी चाहिए थी। लेकिन रामनिवास के हिस्से में 25 बीघा 15 विस्वा आराजी दी है।


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कल्याण के हिस्से में 14 बीघा 10 विस्वा आराजीयात आई है तथा मूल्या के हिस्से में 28 बीघा आराजीयात आई है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। कल्याण ने बंटवारे पर कोई अगूठा निशानी नहीं की थी। फर्जी अगूठा निशानी बनाई है क्योंकि कल्याण मौजूद होता तो कम आराजीयात बंटवारे में क्यों लेता। अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध बंटवारा किया है अपीलांट के निर्णय की डिक्ली पारित नहीं की है। घीस्या जिन्सी से अपीलांट की आराजीयात का कोई संबंध वास्ता नहीं है फिर भी घीस्या व जिन्सी को अपीलांट के बुजुर्गान की आराजीयात में हिस्सा देकर बंटवारा किया है जो गलत है। इसलिए अदालत मातहत का निर्णय खारिज योग्य है। अपीलांट आज भी मौके पर 1/3 हिस्से पर काबिज है। अपीलांट को हल्का पटवारी ने दिनांक 2-2-18 को बताया कि तुम्हारे खाते में 1/3 हिस्से की आराजीयात नहीं है मौके पर 1/3 हिस्से में काबिज हो तब प्रार्थीगण को उक्त निर्णय का इल्म हुआ तो प्रार्थीगण ने रेस्पो0 से कहा कि तुम राजस्व रिकार्ड को सही कराओ तो रेस्पो0 ने जबाब दिया कि अब अभियान आयेगा तब राजस्व अभियान में इन्द्राज दुरुस्त कराके आपके खाते में 1/3 हिस्से की आराजीयात लगवा देंगे। राजस्व अभियान में रेस्पो0 नहीं गये साफ मना कर दिया कि हम राजस्व रिकार्ड सही नहीं करायेगे। इसलिए अपीलांट को अपील पेश करनी पड़ी इसलिए निर्णय की डेट आफ नोलेज से अपील अन्दर मियाद पेश है। कानूनन अनाधिकृत आदेश को कभी भी चलेन्ज किया जा सकता है इसके संबंध में माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित अनेक निर्णयों में स्पष्ट किया गया है जिसकी कोई मियाद नहीं है। कानून मियाद के आधार पर किसी के हक एवं अधिकारों समाप्त नहीं किये जा सकते हैं। अतः अपीलांट की अपील मियाद शुमार मानी जाकर अपील स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ताओं ने बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अपील बिलम्ब से पेश करने के संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मियाद का कोई स्पष्ट एवं विधिक कारण का उल्लेख नहीं किया है। जिससे की बिलम्ब के संबंध में कोई प्रतिउत्तर दिया जा सके। चूंकि विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात रही है जिसमें आपसी सहमति से बंटवारा किया गया है। जब पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा होता है तो कानूनन उसकी अपील नहीं की जा सकती है। जिन भाईयों के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा हुआ है उनको मरे अर्सा दराज का समय हो चुका है। उक्त सहमति के आधार पर हुए बंटवारे का राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका है एवं काश्तकार बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। यदि अब उक्त बंटवारे को अपील की आड में निरस्त किया जाता है तो पक्षकारों को काफी असुविधा होगी क्योंकि बंटवारे अनुसार काश्तकारों द्वारा अपने अपने हिस्से पर पुख्ता निर्माण करवाकर बोरिंग आदि लगवाकर बिजली कनेक्शन लिये हुए हैं एवं अपने अपने हिस्से की भूमि को काफी पैसा लगाकर काश्त योग्य बनाया गया है। अपीलांट का कथन रहा कि बंटवारे में रेस्पो0 संख्या 14,15 व 16 को भूमि दी गई है जबकि वह खातेदार नहीं है। अपीलांट का यह कथन गलत है क्योंकि रेस्पो0 14 ता 16 के बुजुर्गान उक्त आराजीयात में संयुक्त खातेदार थे जिनको हिस्से अनुसार भूमि



राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

बंटवारे में दी गई है। इस प्रकार अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील आपसी सहमति के आधार पर हुए बंटवारे के विरुद्ध पेश की गई है जिसकी अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय एवं अधिनस्थ की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात अपीलान्त संख्या 1 लगायत 13 के बुर्जगान रामनिवास, कल्याण, मूल्या पिसरान नन्दा माली की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात रही है। जिसका विधिवत बंटवारा उनके द्वारा आपसी सहमति से दौरान राजस्व अभियान में कराया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो बंटवारा किया गया है उसके अवलोकन से जाहिर है कि संयुक्त खातेदारी की आराजीयात में से रामनिवास को 25 बीघा 15 विस्वा, कल्याण को 14 बीघा 10 विस्वा तथा मूल्या को 28 बीघा 1 विस्वा एवं घीस्या, जंसी पुत्रान श्योबक्श को 2 बीघा 6 विस्वा दी गई है। जो कुल रकबा 71 बीघा 2 विस्वा होती है। जबकि उनके संयुक्त खाते में भूमि 71 बीघा 6 विस्वा भूमि रही है। जो जमाबंदी सम्वत 2033 से 2036 से स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये बंटवारे में संयुक्त खातेदारों को भूमि किसी को कम एवं किसी को ज्यादा दी गई है। जबकि बंटवारे में संयुक्त खातेदारों को भूमि का विभाजन बराबर बराबर किया जाना चाहिए। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया बंटवारा विधिक बंटवारा नहीं है। संयुक्त खातेदारों को सम्पूर्ण भूमि में से बराबर का हिस्सा दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये बंटवारे का निरस्त कर विवादित भूमि के बाबत मौके एवं कब्जे के अनुसार पुनः तहसीलदार से बंटवारा स्कीम प्राप्त कर विधिवत बंटवारा करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्त रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिलाधीश सवाई माधोपुर के मु०नं० 464/81 में पारित निर्णय दिनांक 16.2.81 को निरस्त किया जाता है। चूंकि विवादित आराजीयात वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर के क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में खाता संख्या 734 लगायत 737 ग्राम मलारना चौड के संयुक्त खातेदारों की आराजीयात की मौके एवं कब्जे की रिपोर्ट के आधार बंटवारा स्कीम प्राप्त की जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर के यहाँ दिनांक 16.6.25 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 19.5.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर प्राधिकारी